उद्योगों की स्थापना के साथ बड़ी संख्या में मिला लोगों को रोजगार: केशव प्रसाद मौर्य

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देकर अनेक उल्लेखनीय कार्य किये जा रहे हैं और बहुत ही सार्थक व उत्साहजनक उपलब्धियां हासिल की गई हैं । भारी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना कराकर अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा रहा है ।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट 2018 में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के उद्यमियों द्वारा 284 एमओयू हस्ताक्षरित करते हुए उद्योगों की स्थापना के लिए 15182.54 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश की इच्छा व्यक्त की गई है जिसमें से 164 उद्यमियों द्वारा प्रदेश में पूंजी निवेश प्रारंभ कर दिया गया है इनमें से 123 व्यवसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है । 11 व्यवसायिक उत्पादन हेतु तैयार हो चुकी

है और 30 में निर्माण कार्य चल रहा है।

प्रथम ग्राउंड बेकिंग समारोह के पश्चात 14 एमओयू में से 13 इकाइयों ने व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है एजिसमें लगभग 3524.57 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है। इसमें लगभग 28 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं 88 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो रहा है। द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में ज्योति ग्राउंड दीवारों में खाद्य प्रसंस्करण की 42 परियोजनाओं में से 27 में व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। जिनमे 3064.55 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है और कुल पूंजी निवेश 3565.03 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, इससे लगभग 25 हजार प्रत्यक्ष एवं 76 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए हैं। एमओयू के तृतीय चरण में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की 225 इकाइयां है जिनसे 11209.16 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश प्रस्तावित है, इनमें से 83 ने व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। 8 व्यावसायिक उत्पादन हेतु तैयार हैं और 22 मे निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें लगभग 89 हजार प्रत्यक्ष एवं 280 हजार अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो रहा है । प्रदेश सरकार के प्रयासों से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत 45 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है। परियोजना प्रस्तावों के माध्यम से प्रदेश में लगभग 1054.77 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिनमें एक लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा तथा प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को अधिकतम अवस्थापना सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।